WARY): (a) and (b) A decision has been taken to set up a joint venture company by selected public enterprises with Non-Resident Indians for specialised management and technological services for better performance of Indian Public Enterprises. Other details regarding setting up of the joint venture company and its activities are yet to be concretised.

Amount spent by Public Enterprises on Research and Development

671. SHRI DINKARRAO GOVINDRAO PATIL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the amount of money spent by Public Enterprises under his Ministy on research and development during the last one year; and

(b) the results achieved so far in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (PROF. K. K. TEWARY): (a) and (b) The Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी विनियोजन

672. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अब तक कुल कितने धन का विनियोजन किया गया है और प्रत्येक में घाटे और लाभ की संचित राशि क्या है ;

(ख) क्या सरकार स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई क़दम उठा रही है; और

(ग) क्या यह सच है कि इन उपक्रमों हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा संबंधी योजनाओं को 18 वर्षों में पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) लोक उद्यम सर्वेक्षण 1984-85 के अनुसार 31-3-1985 को उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में कुल 3919.12 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश किया गया है। 31-3-1985 को सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों की संचित प्रारक्षित निधि तथा बचत राशि (विशिष्ट प्रारक्षित निधि को छोड़कर) और संचित हानि क्रमश: 793.11 करोड़ रुपये 1,431.55 करोड रुपये थी।

(ख) सरकार ने सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए अनेक सदुपाय किये हैं। इन सदुपायों में अन्य बातों के साथसाथ शामिल हैं—कार्य निष्पादन का विभिन्न स्तरों पर गहन परिवीक्षण करना तथा सम्बद्ध विभागों द्वारा आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना और और गतिरोध, यदि कुछ हों, तो उन्हें दूर करने के लिए समुचित उपाय करना, संरचनात्मक पुनर्गठन करना जैसे धारक कम्पनियाँ बनाना, प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाना, संयंत्र तथा उपस्कर का आधुनिकिरण एवं पुनर्स्थापन करना, समुन्नत अनुरक्षण पद्धतियां अपनाना, माल सूची नियंत्रण, उत्पाद विविधीकरण और उत्पाद-मिश्र में सुधार लाना, कार्मिकों को प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षिण दिलाना, लागत नियंत्रण एवं लागत घटाने पर जोर देना तथा प्रबंध में कार्मिकों की भागीदारी को प्रोत्साहन देना।

(ग) जी नहीं। उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्तरोत्तर कार्यान्वयन के सभी सम्भव प्रयास कर रहे हैं।